

प्रतिलिपि क्रमांक 1606-3जी0 एस0-1-75, दिनांक 24-4-1975 मुख्य सचिव हरियाणा की ओर से वित्तायुक्त राजस्व तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा को प्रेषित ।

विषय :—सेवा निवृत्त उपरान्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की पुनः नियुक्ति ।

क्या वित्तायुक्त, राजस्व तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव, उपरोक्त विषय पर संयुक्त पंजाब के अशा0 क्रमांक 9246-जी 11-57 दिनांक 8 जनवरी 1958 द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर ध्यान देंगे ।

2. ऐसा देखने में आया है कि पुनः नियुक्ति सम्बन्धी मामले बड़ी संख्या में मुख्य सचिव, (सामान्य सेवाएं शाखा -1) को प्रशासनिक विभागों द्वारा भेजे जाते हैं जिनमें पुनः नियुक्ति के लिए लोकहित में नितान्त आवश्यकता नहीं होती है । पुनः नियुक्ति के लिए हिदायतों के परा 2 (सी) में कुछ शर्तें लगाई गई हैं जिनकी रोशनी में प्रत्येक विभाग को अपने पुनः नियुक्ति सम्बन्धी मामलों की जांच करना होता है। यहां पर ये सभी शर्तें पूरी होती हैं वहां पर प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग की सहमति से पुनः नियुक्ति सम्बन्धी मामलों में आदेश जारी कर सकते हैं । जिन मामलों में इन शर्तों में से कुछ शर्तें पूरी नहीं होती हैं उनके बारे प्रशासकीय विभागों को पूर्ण औचित्य देना होता है तथा इनको पूरा न होने के लिए ढील के लिए प्रस्ताव भेजना होता है। लेकिन साधारण तथा यह देखने में आया है कि इन शर्तों की रोशनी में मामलों की जांच नहीं की जाती है और खास तौर पूर्ण औचित्य सहित यह नहीं बताया जाता है कि अमुक शर्त में इस कारण ढील की आवश्यकता है ।

3. अतः उनसे अनुरोध है कि प्रथम तो पुनः नियुक्ति संबंधी मामलों में नितान्त आवश्यकता होने पर और केवल लोक हित में ही विचार किया जाए । दूसरे इन हिदायतों के अनुसार उनकी जांच की जाये तथा खास तौर पर उन शर्तों के पूरा न होने पर उनके बारे पूर्ण औचित्य तथा ढील का प्रस्ताव किया जाये । इसके अतिरिक्त प्रत्येक मामलों को स्वतः स्पष्ट रूप में (एक फालतू प्रति सहित) केवल संबंधित प्रशासकीय सचिव के माध्यम से ही मुख्य सचिव को मंत्रणा के लिये भेजा जाए । ऐसा न होने पर प्रत्येक प्रस्ताव को बिना किसी प्रकार की मंत्रणा संबंधित विभाग को लौटा दिया जावेगा और इस प्रकार सारी देरी के लिये वे ही जिम्मेवार होंगे ।

4. यह भी अनुरोध किया जाता है कि पुनः नियुक्ति संबंधी त्रिमासिक रिपोर्टें बिना चुक यथा समय पत्र भेजी जाए । ऐसा देखने में आया है कि इस रिपोर्ट को बहुत से विभाग नियमानुसार नहीं भेज रहे । अतः कृपया सुनिश्चित किया जाए कि आगे से यह नियमित रूप से भेजी जायेगी ।

5. कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें ।